प्रसव के दौरान

प्रति मिनट एक महिला की मौत

शक्ति मनीष वैद्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रसव से जुड़ी समस्याओं के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 5 लाख 85 हज़ार महिलाओं की असमय मौत हो जाती है। यानी प्रसव के दौरान दुनिया में प्रति मिनट एक महिला की मौत हो जाती है। इनमें से करीब 99 प्रतिशत मौतें तो विकासशील देशों में होती है।

विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव व जागरूकता की कमी दो ऐसे बड़े कारण है जिनके चलते लाख कोशिशों के बावजूद जच्चा मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर कम नहीं हो पा रही है। मातृत्व सुख की तमन्ना में हर साल विकासशील देशों की करीब 30 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था या मातृत्व से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आती है। ये बीमारियां ऐसी हैं जिनका समय पर निदान व चिकित्सा हो, तो आसानी से इनसे बचाव किया जा सकता है और इलाज किया जा सकता है।

लेकिन विकासशील देशों के अधिकांश इलाकों में न तो स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित नेटवर्क है और न ही लोगों का मैदानी स्वास्थ्य अमले पर विश्वास। लिहाज़ा मौतों का यह आंकड़ा इस भयावह स्तर पर है।

तमाम कोशिशों के बाद भी जच्चा मृत्यु दर अकेले भारत में ही 1 लाख प्रसवों पर 540 तक पहुंच गई है जबकि पहले यह 424 प्रति 1 लाख प्रसव थी। हर साल प्रसव के दौरान हमारे देश में करीब 1 लाख 30 हज़ार माताओं की मौत हो जाती हैं। मौतों के इन आंकड़ों में सबसे भयावह तस्वीर ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों की है। यहां सरकार का मैदानी स्वास्थ्य अमला तैनात तो है लेकिन जच्चा मृत्यु दर रोक पाने में सक्षम नहीं है। न ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरी संसाधन है और न ही प्रशिक्षित दाइयां। गांवों से स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी काफी अधिक होती हैं और गांवों में प्रसव के दौरान ताबड़-तोड़ यातायात की व्यवस्था भी नहीं हो पातीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य के लिए प्रति व्यक्ति खर्च शहरी क्षेत्रों की तुलना में 7 गुना से भी कम है और यहां डॉक्टरों की संख्या भी शहरों की तुलना में 6 गुना कम है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में बिस्तर करीब 15 गुना कम है इसलिए कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब गांवों में प्रसूता केंद्र तक तो पहुंच जाती है लेकिन वहां जगह न मिलने के कारण खुले में ही प्रसव हो जाता है। पहुंच विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूता को अस्पताल तक ले जाने में कई बार रास्ते में प्रसव हो जाता है जिससे कभी नवजात तो कभी प्रसूता की ही मौत हो जाती हैं।

आदिवासी ग्रामीण समाजों में टोने टोटके वगैरह का लम्बा सिलसिला है। सरकार का मैदानी स्वास्थ्य अमला न तो आज तक इन भ्रांतियों को दूर कर पाया है और न ही प्रशिक्षित दाइयां प्रसव की आधुनिक व सुरक्षित तकनीकों का इस्तेमाल कर पाती हैं। गर्भावस्था में उचित पोषण न मिल पाने से महिलाएं प्रसव के दौरान एनीमिया और पीलिया जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। गंभीर कुपोषण का असर गांवों में दलित वर्ग की महिलाओं में करीब डेढ़ गुना ज़्यादा होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रसव के दौरान महिलाओं की मौतें रोकने के लिए प्रति महिला एक साल का खर्च केवल तीन डालर यानी करीब 150 रुपए आएगा लेकिन फिलहाल यह भी नहीं मिल पा रहा है। ***(स्रोत फीचर्स)***